

International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन

अविनाश कुमार सिन्हा

असिस्टेंट प्रोफेसर

ज्योति प्रकाश महिला बी. एड कॉलेज, चियाकी, पलामू, झारखंड

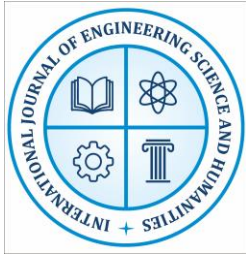
सारांश

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यद्यपि नामांकन दर में वृद्धि हुई है, फिर भी ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों—जैसे अपर्याप्त अधोसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शिक्षण-अधिगम संसाधनों का अभाव, डिजिटल विभाजन, सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ तथा विद्यार्थियों की अनियमित उपस्थिति—का विश्लेषण करना है। शोध में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि संसाधनों की असमान उपलब्धता, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात में असंतुलन तथा अभिभावकों की सीमित शैक्षिक जागरूकता शिक्षा की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अध्ययन के निष्कर्ष इस ओर संकेत करते हैं कि प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप, शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी समावेशन तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता, शैक्षिक समस्याएँ, अधोसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की आधारशिला मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है बल्कि समाज को जागरूक, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना तथा हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना रहा है। इसके बावजूद, यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की भौतिक अधोसंरचना, जैसे कक्षाओं की संख्या, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी शिक्षा के प्रभावी संचालन में बाधा उत्पन्न करती है। इसके साथ ही प्रशिक्षित एवं प्रेरित शिक्षकों का अभाव, उच्च शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात तथा



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

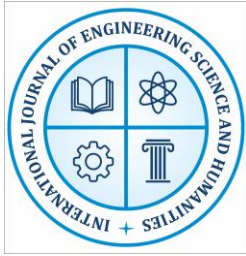
शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को कमजोर बनाती है। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बाल श्रम, लैंगिक असमानता एवं अभिभावकों की सीमित शैक्षिक जागरूकता भी विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और सीखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। वर्तमान डिजिटल युग में, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट सुविधाओं की कमी ने शहरी एवं ग्रामीण शिक्षा के बीच अंतर को और अधिक गहरा कर दिया है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिसका प्रभाव उनके शैक्षिक उपलब्धि स्तर एवं भविष्य के अवसरों पर पड़ता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का व्यवस्थित एवं गहन अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, ताकि इन चुनौतियों की पहचान कर प्रभावी समाधान एवं नीतिगत सुधारों के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके।

अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में अत्यंत आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण है, क्योंकि भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और देश का समग्र विकास उसी पर निर्भर करता है। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में विद्यालयों की संख्या, नामांकन दर तथा साक्षरता स्तर में वृद्धि हुई है, फिर भी ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। संसाधनों की कमी, अपर्याप्त अधोसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, शिक्षण विधियों की पारंपरिकता तथा तकनीकी सुविधाओं की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याएँ ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियाँ, लैंगिक असमानता एवं अभिभावकों की सीमित शैक्षिक जागरूकता जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक विद्यार्थियों की निरंतरता और शैक्षिक उपलब्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस संदर्भ में, ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित एक व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक है, ताकि इन समस्याओं की वास्तविक प्रकृति, कारणों एवं प्रभावों को समझा जा सके। यह अध्ययन न केवल शिक्षा प्रशासकों, नीति-निर्माताओं एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि ग्रामीण समुदाय को भी शिक्षा के महत्व एवं गुणवत्ता सुधार की दिशा में जागरूक करेगा। अध्ययन के निष्कर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार हेतु उपयुक्त नीतियाँ, कार्यक्रम एवं हस्तक्षेप विकसित करने में सहायक होंगे। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन सामाजिक समानता, शैक्षिक न्याय एवं सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होता है।

अध्ययन की पृष्ठभूमि

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और इन क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा की स्थिति पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए गए, जिनका उद्देश्य शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा निरक्षरता को समाप्त करना रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या और नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। अनेक ग्रामीण विद्यालय बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षित शिक्षकों, आधुनिक शिक्षण सामग्री एवं प्रभावी



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

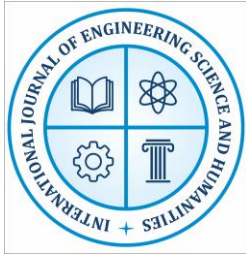
शैक्षणिक पर्यवेक्षण के अभाव से जूझ रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, जैसे गरीबी, अभिभावकों की अशिक्षा, बाल श्रम तथा लैंगिक भेदभाव भी विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही, वैश्वीकरण और डिजिटल क्रांति के वर्तमान युग में शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच बढ़ता अंतर चिंता का विषय बन गया है। इस पृष्ठभूमि में, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, ताकि वर्तमान स्थिति का यथार्थ मूल्यांकन कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु ठोस एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें।

शिक्षा का सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व

शिक्षा समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है, क्योंकि यह व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को दिशा प्रदान करती है। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा व्यक्ति को जागरूक नागरिक बनाती है, जिसमें समानता, सहिष्णुता, सहयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। शिक्षित समाज कुरीतियों, अंधविश्वास, लैंगिक भेदभाव एवं सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने में सक्षम होता है, जिससे सामाजिक समरसता और न्याय को बल मिलता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, बल्कि समाज के विकास में सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मानव संसाधन विकास का सबसे प्रभावी साधन है, जो राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को सुदृढ़ बनाता है। शिक्षित जनसंख्या कुशल कार्यबल का निर्माण करती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और बेरोजगारी तथा गरीबी जैसी समस्याओं में कमी आती है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह नागरिकों में देशभक्ति, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना का विकास करती है। विकासशील देशों के संदर्भ में शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख माध्यम है, जो वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर संतुलित विकास को प्रोत्साहित करता है। वर्तमान वैश्वीकरण और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के युग में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रमुख संकेतक बन चुकी है। अतः शिक्षा का सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न होकर, समग्र सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास तथा राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी देश का उज्ज्वल भविष्य सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करता है।

ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति

भारत में ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति मिश्रित चित्र प्रस्तुत करती है, जहाँ एक ओर नामांकन और विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी अनेक गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सरकारी प्रयासों जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मध्याह्न भोजन योजना, समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है और बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला है। तथापि, मात्र विद्यालयों की उपलब्धता से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हो पाई है। अनेक ग्रामीण विद्यालय आज भी अपर्याप्त अधोसंरचना से जूझ रहे हैं, जहाँ कक्षाओं की



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

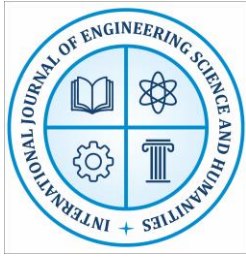
कमी, जर्जर भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का अभाव तथा स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता आम समस्या है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी, उच्च शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात तथा शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षण पद्धतियाँ प्रायः पारंपरिक और परीक्षा-केन्द्रित बनी हुई हैं, जिससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और व्यावहारिक ज्ञान का समुचित विकास नहीं हो पाता। सामाजिक-आर्थिक कारक, जैसे गरीबी, अभिभावकों की अशिक्षा, बाल श्रम और मौसमी पलायन, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और निरंतरता में बाधा उत्पन्न करते हैं। डिजिटल युग में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्ट कक्षाओं की सीमित उपलब्धता ने शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच अंतर को और अधिक बढ़ा दिया है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण विद्यार्थियों की सीखने की उपलब्धियाँ अपेक्षाकृत कम रहती हैं और वे उच्च शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों में पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार, ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति यह संकेत देती है कि पहुँच के साथ-साथ गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित समग्र एवं प्रभावी हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है।

साहित्य समीक्षा

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित अध्ययन लंबे समय से शिक्षा शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। अग्रवाल (2000) ने भारत में शैक्षिक योजना पर अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा की गुणवत्ता केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाने से सुनिश्चित नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए दीर्घकालिक एवं संतुलित शैक्षिक नियोजन आवश्यक है। उनके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का असमान वितरण, प्रशासनिक कमजोरियाँ और स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा शिक्षा के विकास में प्रमुख बाधाएँ रही हैं। यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि यदि योजनाएँ जमीनी स्तर की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जातीं, तो वे अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहती हैं। यह दृष्टिकोण ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को समझने की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

ट्रेज़ और सेन (2013) ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सामाजिक और आर्थिक विकास के व्यापक संदर्भ में विश्लेषित किया है। उनके अध्ययन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि शिक्षा केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता को उन्होंने गरीबी, सामाजिक असमानता और सरकारी सेवाओं की अपर्याप्तता से जोड़ा है। उनका अध्ययन यह दर्शाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के बिना मानव विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। ग्रामीण शिक्षा की उपेक्षा से क्षेत्रीय असमानताएँ और अधिक गहरी हो जाती हैं, जिससे समाज के वंचित वर्ग मुख्यधारा से बाहर रह जाते हैं। यह दृष्टिकोण ग्रामीण शिक्षा को सामाजिक विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने में सहायक है।

भारत सरकार द्वारा लागू किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहल माना जाता है। इस अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। हालांकि, विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन में गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

झा और पार्वती (2018) ने ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए पाया कि नामांकन में वृद्धि के बावजूद सीखने के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने शिक्षकों की कमी, अधोसंरचना की दुर्बलता और निगरानी तंत्र की कमजोरी को शिक्षा की निम्न गुणवत्ता के प्रमुख कारणों के रूप में रेखांकित किया है। यह अध्ययन इस तथ्य को उजागर करता है कि कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ गुणवत्ता पर केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप भी आवश्यक हैं।

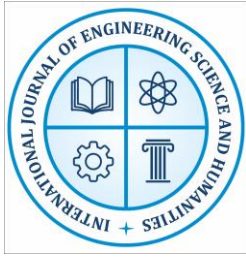
किंगडन (2007) और मेहरोत्रा (2006) के अध्ययनों ने भारत में स्कूली और प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर को रेखांकित किया है। किंगडन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक अनुपस्थिति, सीमित संसाधन और सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ सीखने के परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। वहीं, मेहरोत्रा ने प्राथमिक शिक्षा सुधारों के बावजूद गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के बने रहने की ओर संकेत किया है। MHRD (2018) और NCERT (2017) की रिपोर्टें भी यह दर्शाती हैं कि ग्रामीण विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम शहरी विद्यार्थियों की तुलना में कमजोर हैं, विशेष रूप से भाषा और गणित जैसे मूलभूत विषयों में। इन सभी अध्ययनों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता एक बहुआयामी समस्या है, जिसके समाधान के लिए संरचनात्मक सुधार, शिक्षक सशक्तिकरण और सीखने के परिणामों पर केंद्रित नीतियाँ अनिवार्य हैं।

शिक्षा नीतियों एवं सरकारी योजनाओं की भूमिका

● राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का ग्रामीण शिक्षा पर प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह नीति समावेशी, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के निर्माण पर बल देती है, जिससे ग्रामीण और वंचित वर्गों तक शिक्षा के लाभ पहुँच सकें। NEP में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षण, तथा सीखने के परिणामों पर आधारित पाठ्यक्रम की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त, नीति में बहु-विषयक एवं कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे ग्रामीण विद्यार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान, रोजगारोन्मुख कौशल और आत्मनिर्भरता का विकास संभव हो सके। शिक्षक प्रशिक्षण, सतत व्यावसायिक विकास और तकनीकी एकीकरण पर दिया गया विशेष जोर ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री पहुँचाने की परिकल्पना भी ग्रामीण शिक्षा के लिए नई संभावनाएँ प्रस्तुत करती है।

● सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं ने नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति सुधारने और विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति कार्यक्रम तथा विद्यालय अधोसंरचना विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इन योजनाओं ने विशेष रूप से बालिका शिक्षा और सामाजिक रूप से वंचित समूहों की भागीदारी बढ़ाने में सकारात्मक योगदान दिया है। तथापि, इन योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि कई स्थानों पर क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याएँ, प्रशासनिक अक्षमताएँ और निगरानी की कमी बनी हुई हैं, जिससे योजनाओं का अपेक्षित लाभ सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता। अतः आवश्यक है कि इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा नियमित मूल्यांकन के माध्यम से नीतिगत सुधार किए जाएँ, ताकि ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता में वास्तविक और स्थायी सुधार संभव हो सके।

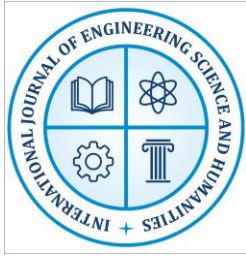
ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन

● संसाधनों, शिक्षकों एवं उपलब्ध सुविधाओं की तुलना

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि दोनों के बीच संसाधनों, शिक्षकों और उपलब्ध सुविधाओं के स्तर पर उल्लेखनीय असमानता विद्यमान है। शहरी विद्यालयों में सामान्यतः बेहतर भौतिक अधोसंरचना, पर्याप्त कक्षाएँ, सुसज्जित पुस्तकालय, आधुनिक प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर कक्ष, इंटरनेट सुविधा और स्मार्ट कक्षा जैसी व्यवस्थाएँ उपलब्ध होती हैं, जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती हैं। इसके विपरीत, अनेक ग्रामीण विद्यालय बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझते हैं, जहाँ जर्जर भवन, सीमित शिक्षण सामग्री, प्रयोगात्मक संसाधनों की कमी और डिजिटल सुविधाओं का अभाव आम समस्या है। शिक्षकों के संदर्भ में भी स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षित, विषय-विशेषज्ञ और अपेक्षाकृत प्रेरित शिक्षक उपलब्ध होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की कमी, उच्च शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात तथा शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, सह-शैक्षिक गतिविधियाँ, परामर्श सेवाएँ और करियर मार्गदर्शन जैसी सुविधाएँ शहरी विद्यालयों में अधिक सुलभ होती हैं, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होती हैं।

● सीखने के परिणामों में अंतर

ग्रामीण और शहरी शिक्षा व्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों और शिक्षण वातावरण के अंतर का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों पर पड़ता है। शहरी विद्यार्थियों में सामान्यतः साक्षरता स्तर, गणितीय एवं भाषाई दक्षता, तकनीकी कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर पाया जाता है। इसके विपरीत, ग्रामीण विद्यार्थियों को सीमित संसाधनों, पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरीबी, अभिभावकों की अशिक्षा, बाल श्रम और अनियमित उपस्थिति जैसी समस्याएँ ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

प्रभावित करती हैं। परिणामस्वरूप, ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक उपलब्धियों का अंतर बना रहता है, जो उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों में असमानता को जन्म देता है। अतः यह तुलनात्मक अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में संतुलन स्थापित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की समान उपलब्धता, शिक्षक सशक्तिकरण और सीखने के परिणामों पर केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक हैं।

ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ

● अधोसंरचना की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली सबसे प्रमुख समस्या विद्यालयों की अपर्याप्त अधोसंरचना है। अनेक ग्रामीण विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाओं का अभाव, जर्जर भवन, बैठने की समुचित व्यवस्था का न होना, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं की कमी जैसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली तथा खेल के मैदान जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव विशेष रूप से बालिकाओं की उपस्थिति और निरंतरता को प्रभावित करता है। भौतिक संसाधनों की यह कमी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में बाधा उत्पन्न करती है और विद्यार्थियों के सीखने के वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

● प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव

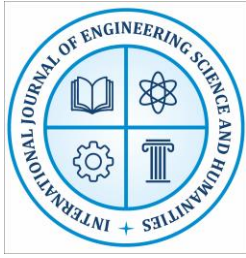
ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी है। कई ग्रामीण विद्यालयों में विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों का अभाव है, जिससे पाठ्यक्रम का समुचित शिक्षण नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति और सीमित प्रशिक्षण अवसर शिक्षण की प्रभावशीलता को कम करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों, मूल्यांकन तकनीकों और बाल-केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण की जानकारी के अभाव में शिक्षक विद्यार्थियों की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं।

● डिजिटल एवं तकनीकी संसाधनों की कमी

वर्तमान डिजिटल युग में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता शिक्षा की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक बन चुकी है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल एवं तकनीकी सुविधाओं की भारी कमी पाई जाती है। अधिकांश ग्रामीण विद्यालयों में कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट कक्षाएँ और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं होती। डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही आधुनिक शिक्षण संसाधनों का लाभ नहीं उठा पाते। इससे शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच डिजिटल विभाजन और अधिक गहरा हो जाता है।

● सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ

ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने में सामाजिक-आर्थिक कारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीबी, बेरोजगारी, अभिभावकों की अशिक्षा, बाल श्रम और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और अध्ययन में बाधा



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

उत्पन्न करती हैं। कई परिवारों में बच्चों से घरेलू या कृषि कार्य कराए जाते हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, लैंगिक असमानता और सामाजिक रूढ़ियाँ विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

● विद्यालय छोड़ने की समस्या

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने की समस्या शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। आर्थिक कठिनाइयाँ, शैक्षिक रुचि की कमी, निम्न गुणवत्ता वाला शिक्षण, दूरी पर स्थित विद्यालय और सामाजिक दबाव विद्यार्थियों को बीच में ही शिक्षा छोड़ने के लिए विवश करते हैं। यह समस्या उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अधिक गंभीर रूप में देखी जाती है। विद्यालय छोड़ने की बढ़ती दर न केवल साक्षरता स्तर को प्रभावित करती है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के भविष्य के अवसरों को भी सीमित कर देती है।

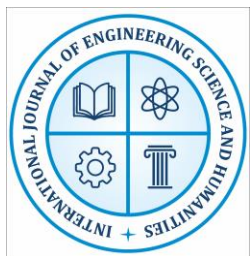
● शैक्षणिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन की कमी

ग्रामीण विद्यालयों में प्रभावी शैक्षणिक पर्यवेक्षण और अकादमिक समर्थन तंत्र का अभाव भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। निरीक्षण, मार्गदर्शन और मूल्यांकन की कमजोर व्यवस्था के कारण शिक्षण की कमियों की समय पर पहचान नहीं हो पाती। शिक्षकों के लिए परामर्श, नवाचार और व्यावसायिक विकास के अवसर सीमित होने से शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता। अतः इन सभी समस्याओं का समग्र समाधान ही ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सार्थक कदम सिद्ध हो सकता है।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण करने हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति को अपनाया गया है। अध्ययन का स्वरूप मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिससे व्यापक और विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकें। द्वितीयक आँकड़ों के स्रोतों में भारत सरकार की रिपोर्टें, शिक्षा मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आँकड़े, ASER रिपोर्ट, NCERT एवं NIEPA की रिपोर्टें, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र, पुस्तकों तथा विश्वसनीय जर्नलों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के लिए ग्रामीण शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे अधोसंरचना, शिक्षक उपलब्धता, शैक्षणिक संसाधन, डिजिटल सुविधाएँ, सामाजिक-आर्थिक कारक एवं विद्यालय छोड़ने की दर से जुड़े आँकड़ों का संकलन किया गया। एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, तुलनात्मक एवं वर्णनात्मक विधियों के माध्यम से किया गया, ताकि ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति और उससे जुड़ी समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। अध्ययन में तालिकाओं के माध्यम से परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे निष्कर्षों को सरल और स्पष्ट रूप में व्याख्यायित किया जा सके। इस पद्धति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

परिणाम और चर्चा



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

तालिका 1: ग्रामीण विद्यालयों में अधोसंरचना सुविधाओं की स्थिति (प्रतिशत में)

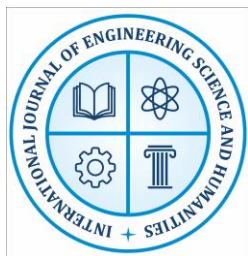
सुविधाएँ	उपलब्ध विद्यालय (%)	अनुपलब्ध विद्यालय (%)
पक्के विद्यालय भवन	72	28
पर्याप्त कक्षाएँ	58	42
पुस्तकालय सुविधा	35	65
प्रयोगशाला	29	71
स्वच्छ पेयजल	76	24
शौचालय सुविधा	69	31

तालिका 1 ग्रामीण विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक अधोसंरचना की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। आँकड़ों के अनुसार, यद्यपि 72 प्रतिशत विद्यालयों में पक्के भवन उपलब्ध हैं, फिर भी 28 प्रतिशत विद्यालय अभी भी इस मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। केवल 58 प्रतिशत विद्यालयों में ही पर्याप्त कक्षाएँ उपलब्ध हैं, जिससे भीड़भाड़ और बहु-स्तरीय शिक्षण की समस्या उत्पन्न होती है। पुस्तकालय और प्रयोगशाला जैसी शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जहाँ क्रमशः 65 प्रतिशत और 71 प्रतिशत विद्यालयों में इनका अभाव पाया गया है। यद्यपि पेयजल (76%) और शौचालय (69%) की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, फिर भी इन सुविधाओं की अनुपलब्धता शेष विद्यालयों में विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं, की उपस्थिति और सीखने के वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

तालिका 2: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक एवं शैक्षणिक संसाधनों की स्थिति

संकेतक	स्थिति
औसत शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात	1:38
प्रशिक्षित शिक्षक (%)	61
अप्रशिक्षित शिक्षक (%)	39
नियमित शिक्षक उपस्थिति (%)	67
डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध विद्यालय (%)	32

तालिका 2 ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक संसाधनों की स्थिति को उजागर करती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। औसत शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 1:38 पाया गया है, जो प्रभावी शिक्षण के लिए अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है। केवल 61 प्रतिशत शिक्षक ही प्रशिक्षित हैं, जबकि 39 प्रतिशत अप्रशिक्षित शिक्षकों की उपस्थिति शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति 67 प्रतिशत तक सीमित है, जिससे



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में निरंतरता बाधित होती है। डिजिटल शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता केवल 32 प्रतिशत विद्यालयों तक सीमित है, जो यह दर्शाती है कि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था तकनीकी दृष्टि से काफी पीछे है। यह स्थिति शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच असमानता को और अधिक गहरा करती है।

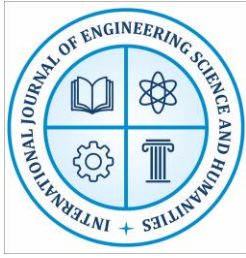
तालिका 3: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने के प्रमुख कारण (प्रतिशत में)

कारण	प्रतिशत (%)
आर्थिक गरीबी	34
बाल श्रम / घरेलू कार्य	21
विद्यालय की दूरी	15
शिक्षा की निम्न गुणवत्ता	18
सामाजिक एवं पारिवारिक कारण	12

तालिका 3 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने की समस्या के प्रमुख कारणों को प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करती है। आँकड़ों से स्पष्ट है कि आर्थिक गरीबी सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण 34 प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा बीच में छोड़ने को विवश होते हैं। बाल श्रम और घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी 21 प्रतिशत मामलों में विद्यालय छोड़ने का कारण बनती है, जो ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक मजबूरियों को दर्शाती है। विद्यालय की दूरी 15 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए बाधा बनती है, विशेषकर दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में। शिक्षा की निम्न गुणवत्ता 18 प्रतिशत मामलों में विद्यार्थियों की रुचि कम कर देती है, जबकि सामाजिक एवं पारिवारिक कारण 12 प्रतिशत तक योगदान करते हैं। ये कारण मिलकर ग्रामीण शिक्षा की निरंतरता और गुणवत्ता दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं के इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा की पहुँच में विस्तार के बावजूद गुणवत्ता का स्तर अभी भी अपेक्षित मानकों तक नहीं पहुँच पाया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था अनेक परस्पर जुड़ी चुनौतियों से प्रभावित है, जिनमें अधोसंरचना की कमी, प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों का अभाव, डिजिटल और तकनीकी संसाधनों की सीमित उपलब्धता तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ प्रमुख हैं। विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे उनकी रुचि और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके साथ ही, उच्च शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, सीमित प्रशिक्षण अवसर और शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को



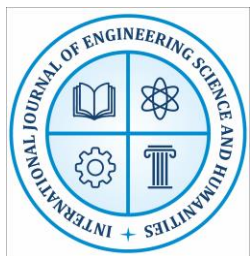
International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

कम कर देती है। डिजिटल युग में तकनीकी संसाधनों की कमी ने ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच अंतर को और अधिक गहरा कर दिया है, जिससे ग्रामीण विद्यार्थी आधुनिक ज्ञान, कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक अवसरों से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक-आर्थिक कारक जैसे गरीबी, अभिभावकों की अशिक्षा, बाल श्रम, लैंगिक असमानता और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और शैक्षिक निरंतरता में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय छोड़ने की समस्या बनी रहती है। समग्र रूप से यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केवल नीतिगत घोषणाएँ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, अधोसंरचना विकास, शिक्षक सशक्तिकरण, तकनीकी समावेशन और समुदाय की सक्रिय सहभागिता पर आधारित समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। ऐसे प्रयासों के माध्यम से ही ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित कर शैक्षिक समानता तथा सतत राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ

1. अग्रवाल, वाई. (2000). भारत में शैक्षिक योजना. नई दिल्ली, भारत: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी.
2. ड्रेज़, जे., और सेन, ए. (2013). एक अनिश्चित गौरव: भारत और उसके विरोधाभास. प्रिंसटन, NJ: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. भारत सरकार. (2009). बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. नई दिल्ली, भारत: कानून और न्याय मंत्रालय.
4. झा, पी., और पार्वती, पी. (2018). ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 53(14), 44–52.
5. किंगडन, जी. जी. (2007). भारत में स्कूली शिक्षा की प्रगति. ऑक्सफोर्ड रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, 23(2), 168–195.
6. मेहरोत्रा, एस. (2006). भारत में प्राथमिक शिक्षा में सुधार. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 41(37), 3849–3856.
7. MHRD. (2018). शैक्षिक आँकड़े एक नज़र में. नई दिल्ली, भारत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
8. NCERT. (2017). प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणाम. नई दिल्ली, भारत: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद.
9. PROBE टीम. (2011). भारत में बुनियादी शिक्षा पर सार्वजनिक रिपोर्ट. नई दिल्ली, भारत: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
10. रामचंद्रन, वी. (2012). भारत में शिक्षक प्रेरणा. नई दिल्ली, भारत: अजीम प्रेमजी फाउंडेशन.



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

11. तिलक, जे. बी. जी. (2015). भारत में शिक्षा, असमानता और विकास. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 40, 136–145.
12. UNESCO. (2015). सभी के लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट. पेरिस, फ्रांस: UNESCO.
13. बनर्जी, आर., और डुफ्लो, ई. (2013). पुअर इकोनॉमिक्स: ग्लोबल गरीबी से लड़ने के तरीके पर एक रेडिकल पुनर्विचार। न्यूयॉर्क, NY: पब्लिकअफेयर्स।
14. गोविंदा, आर., और बंद्योपाध्याय, एम. (2011). भारत में प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच: देश का विश्लेषणात्मक रिव्यू। CREATE पाथवेज़ टू एक्सेस रिसर्च मोनोग्राफ नंबर 22. नई दिल्ली, भारत: NUEPA।
15. कुमार, के. (2005). 21वीं सदी की शुरुआत में शिक्षा की गुणवत्ता: भारत से सबका नई दिल्ली, भारत: UNESCO।